ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor = 8.35, January-June 2026, Submitted in January 2026

# भारत-जापान संबंध (2014 से जनवरी 2026 तक): रणनीतिक भागीदारी से व्यापक सहयोग तक की यात्रा

मयंक सिंह, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर ,उत्तर प्रदेश

## सारांश (Abstract):

वर्ष 2014 भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब दोनों देशों ने अपने पारंपरिक आर्थिक सहयोग को "विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी" (Special Strategic and Global Partnership) के स्तर तक उन्नत किया। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत और जापान के संबंधों ने कूटनीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक स्थिरता जैसे अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व विस्तार देखा है। यह शोध-पत्र 2014 से लेकर जनवरी 2026 तक भारत-जापान संबंधों के विभिन्न आयामों—कूटनीतिक पहल, आर्थिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, हिंद-प्रशांत रणनीति, उभरती प्रौद्योगिकियों में सहभागिता तथा सांस्कृतिक संबंधों—का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। साथ ही इस साझेदारी के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं की भी विवेचना की गई है।

**कूट शब्द (Keywords): भारत-जापान संबंध, विशेष रणनीतिक साझेदारी, हिंद-प्रशांत, क्वाड, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग।**

## 1. भूमिका

भारत और जापान के बीच संबंध केवल कूटनीतिक या आर्थिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनकी जड़ें सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान में गहराई से समाई हुई हैं। बौद्ध धर्म के माध्यम से दोनों देशों के बीच सदियों पुराना आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है, जिसने आधुनिक कूटनीतिक संबंधों की नींव को और सुदृढ़ किया। औपचारिक कूटनीतिक संबंध 1952 में स्थापित हुए, परंतु वास्तविक अर्थों में इस साझेदारी ने गति तब पकड़ी जब इक्कीसवीं सदी में वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरण बदलने लगे।

वर्ष 2014 भारत-जापान संबंधों के लिए एक निर्णायक वर्ष सिद्ध हुआ। इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के पश्चात् दोनों देशों ने अपने संबंधों को "वैश्विक साझेदारी" से आगे बढ़ाकर "विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी" के स्तर पर पहुँचाया। इसके पश्चात् से भारत और जापान के मध्य सहयोग के दायरे में निरंतर विस्तार हुआ है—चाहे वह उच्च-गति रेल परियोजनाओं में जापानी तकनीकी सहयोग हो, रक्षा उपकरणों का संयुक्त विकास हो, अथवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अर्धचालक जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में साझेदारी।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य 2014 से लेकर वर्तमान समय तक भारत-जापान संबंधों के विकास-क्रम, उसके प्रमुख आयामों तथा इस साझेदारी के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करना है। यह अध्ययन कूटनीतिक, आर्थिक, रक्षा-सामरिक तथा सांस्कृतिक—इन चार प्रमुख आयामों के माध्यम से इस संबंध की गहराई और व्यापकता को समझने का प्रयास करता है।

## 2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं द्विपक्षीय संबंधों का विकास-क्रम

भारत-जापान संबंधों के विकास को समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात आवश्यक है। औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना 1952 में हुई, किंतु शीत युद्ध के दौरान दोनों देश भिन्न-भिन्न वैश्विक खेमों में होने के कारण संबंधों में वह गहराई नहीं आ सकी जो अपेक्षित थी। शीत युद्ध की समाप्ति तथा भारत की 1991 की आर्थिक उदारीकरण नीति के पश्चात् द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा का संचार हुआ।

वर्ष 2000 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को "वैश्विक साझेदारी" (Global Partnership) के स्तर तक उन्नत किया, जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसके पश्चात् 2006 में वार्षिक शिखर सम्मेलन की व्यवस्था स्थापित की गई, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष एक-दूसरे की राजधानी में मिलकर द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हैं। यह तंत्र आज भी सक्रिय है और भारत-जापान संबंधों की निरंतरता का प्रतीक है।

वर्ष 2011 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA) एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने दोनों देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं तथा निवेश के क्षेत्र में शुल्क-मुक्त एवं उदार व्यापार व्यवस्था की नींव रखी। इस समझौते ने आगे चलकर दोनों देशों के बीच व्यापार को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तथापि, वास्तविक अर्थों में संबंधों को नई दिशा तब मिली जब वर्ष 2014 में दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को "विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी" के स्तर तक उन्नत किया। यह उन्नयन केवल प्रतीकात्मक नहीं था, अपितु इसने आगामी वर्षों में रक्षा, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना तथा हिंद-प्रशांत रणनीति के क्षेत्र में गहन सहयोग की आधारशिला रखी। इसी क्रम में "जापान-भारत विजन 2025" दस्तावेज़ के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए दोनों देशों ने एक साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

**3. 2014 के बाद की कूटनीतिक गतिशीलता**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति में "एक्ट ईस्ट नीति" (Act East Policy) को केंद्रीय स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें जापान को एक स्वाभाविक तथा महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखा गया। वर्ष 2017 में स्थापित "भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम" इसी दिशा में एक ठोस कदम था, जिसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में जापानी तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग को सुनिश्चित करना था। यह फोरम कनेक्टिविटी, अवसंरचना विकास तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को संस्थागत स्वरूप प्रदान करता है।
इसी अवधि में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला ने संबंधों को निरंतर गति प्रदान की। दोनों देशों के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष बारी-बारी से नई दिल्ली और टोक्यो में मिलते रहे हैं, जिसके माध्यम से न केवल पूर्व की प्रगति की समीक्षा होती है, बल्कि नए क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा भी तैयार की जाती है। 29-30 अगस्त 2025 को टोक्यो में आयोजित 15वाँ भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन इस निरंतरता का ताज़ा तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा (Shigeru Ishiba) के बीच व्यापक विचार-विमर्श हुआ। यह वर्ष 2014 में मोदी की पहली जापान यात्रा तथा "विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी" की स्थापना के ठीक एक दशक बाद हुआ सम्मेलन था। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने "अगले दशक के लिए भारत-जापान संयुक्त दृष्टिकोण" (Japan-India Joint Vision for the Next Decade) नामक दस्तावेज़ अपनाया, जिसमें आर्थिक भागीदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता (mobility), पारिस्थितिक स्थिरता, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, स्वास्थ्य, जन-जन संपर्क तथा राज्य-प्रांत सहभागिता—इन आठ प्राथमिकता क्षेत्रों को रेखांकित किया गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने लगभग एक दर्जन से अधिक समझौतों एवं सहमति-पत्रों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए, जो रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई दिशा प्रदान करते हैं।
इन शिखर सम्मेलनों के अतिरिक्त, "2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद" (विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के बीच) भी दोनों देशों के बीच रणनीतिक समन्वय का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। इसका तीसरा दौर 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसके साथ ही रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक भी संपन्न हुई। यह तंत्र दोनों देशों को सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर उच्चस्तरीय संवाद स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है, जो परंपरागत आर्थिक कूटनीति से आगे बढ़कर रणनीतिक विश्वास की गहराई को दर्शाता है। 15वें शिखर सम्मेलन में दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों की कड़ी निंदा भी की, विशेष रूप से 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए, तथा अल कायदा, आईएसआईएस/दाएश, लश्कर-ए-तैयबा तथा जैश-ए-मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध सभी आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध ठोस अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की माँग की।
इस दशक की शुरुआत में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच स्थापित व्यक्तिगत सौहार्द ने भी द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान की। दोनों नेताओं के बीच नियमित शिखर वार्ताओं, आपसी यात्राओं तथा "विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी" के प्रति साझा प्रतिबद्धता ने अगली पीढ़ी के नेतृत्व—जिसमें योशिहिदे सुगा, फुमियो किशिदा तथा वर्तमान प्रधानमंत्री साने

ताकाइची सम्मिलित हैं—के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार किया। इस निरंतरता ने यह सुनिश्चित किया कि जापान में नेतृत्व-परिवर्तन के बावजूद भारत-जापान संबंधों की गति एवं दिशा में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, जो इस साझेदारी की संस्थागत परिपक्वता का प्रमाण है।

**4. आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध**

आर्थिक सहयोग भारत-जापान साझेदारी की आधारशिला रहा है। वर्ष 2011 के व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के पश्चात् द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि दर्ज़ हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 25.15-25.17 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो वर्ष 2020-21 के 15.33 अरब डॉलर की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। कैलेंडर वर्ष 2024 के आँकड़ों के अनुसार भारत का जापान को निर्यात लगभग 5.73 अरब डॉलर तथा जापान से आयात लगभग 19.9 अरब डॉलर रहा। यह आँकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि व्यापार संतुलन अभी भी जापान के पक्ष में झुका हुआ है, जो इस साझेदारी की एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आता है। भारत के प्रमुख निर्यातों में कार्बनिक रसायन, वाहन, एल्युमिनियम उत्पाद तथा मत्स्य उत्पाद सम्मिलित हैं, जबकि आयात में विद्युत मशीनरी, परमाणु रिएक्टर, ताँबा, अकार्बनिक रसायन तथा लौह-इस्पात प्रमुख हैं।

निवेश के क्षेत्र में जापान भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक रहा है। जापान वर्तमान में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के पाँचवें सबसे बड़े स्रोत के रूप में स्थापित है, जिसका वर्ष 2000 से दिसंबर 2024 तक का संचयी निवेश लगभग 43-44 अरब डॉलर रहा है। 29-30 अगस्त 2025 के 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में जापान ने अगले दस वर्षों में भारत के निजी क्षेत्र में लगभग 10 खरब येन (लगभग 68 अरब डॉलर) के निवेश का नया लक्ष्य घोषित किया, जो वर्ष 2022-2026 की पूर्ववर्ती प्रतिबद्धता (लगभग 5 खरब येन) से दोगुना है। इसके अतिरिक्त, भारत जापान की आधिकारिक विकास सहायता (Official Development Assistance - ODA) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है, जिसके माध्यम से मुंबई तथा बेंगलुरु जैसे महानगरों में मेट्रो परियोजनाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ है।

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना (बुलेट ट्रेन), जो जापान की शिंकानसेन तकनीक तथा रियायती ऋण सहायता पर आधारित है, भारत-जापान आर्थिक सहयोग का एक प्रतीकात्मक तथा महत्वाकांक्षी उदाहरण है। यद्यपि इस परियोजना की समय-सीमा को लेकर विभिन्न चुनौतियाँ रही हैं, तथापि यह दोनों देशों के दीर्घकालिक तकनीकी सहयोग की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

हाल के वर्षों में, विशेषकर कोविड-19 महामारी तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के पश्चात्, दोनों देशों ने नवंबर 2024 में विदेश सचिव तथा जापान के तत्कालीन उप-विदेश मंत्री के मध्य "भारत-जापान आर्थिक सुरक्षा संवाद" के प्रथम दौर का आयोजन किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, अगस्त 2025 के 15वें शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने "आर्थिक सुरक्षा पहल" की औपचारिक शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अर्धचालक, गंभीर खनिज तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। साथ ही, CEPA के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित छह उप-समितियाँ—मूल नियम, सीमा-शुल्क प्रक्रिया, तकनीकी विनियम, सेवा व्यापार, व्यापारिक वातावरण में सुधार तथा प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही—नियमित रूप से बैठकें कर रही हैं, ताकि व्यापार असंतुलन को कम करने की दिशा में ठोस प्रगति हो सके।

ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग नए आयाम प्राप्त कर रहा है। भारत से जापान को हरित अमोनिया (Green Ammonia) के निर्यात हेतु प्रथम-श्रेणी का समझौता संपन्न हुआ है, तथा REC लिमिटेड जैसी संस्थाओं ने स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं हेतु जापानी हरित ऋण (Green Loan) भी प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, भारत के डेयरी सहकारी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में बायोगैस एवं जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की योजनाएँ भी प्रगति पर हैं, जो दोनों देशों की ऊर्जा सुरक्षा तथा सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

**5. रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग**

भारत-जापान रक्षा सहयोग ने विगत एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2015 में हस्ताक्षरित "रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता" ने दोनों देशों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके पश्चात् स्थापित "2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद तंत्र" तथा "सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा-पत्र" ने रक्षा संबंधों को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया।

दोनों देश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भाग लेते हैं, जिनमें नौसैनिक अभ्यास "मालाबार" (Malabar), थल सेना अभ्यास "धर्म गार्जियन" (Dharma Guardian) तथा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास "जिमेक्स" (JIMEX) प्रमुख हैं। उदाहरणस्वरूप, 9 अक्टूबर 2024 को विशाखापत्तनम में आयोजित मालाबार-24 अभ्यास तथा सितंबर 2024 में आयोजित बहुपक्षीय वायु अभ्यास "तरंग शक्ति" में जापानी सैन्य प्रतिनिधिमंडलों की सक्रिय भागीदारी रही। ये अभ्यास न केवल दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता को बढ़ाते हैं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करते हैं।

रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि 15 नवंबर 2024 को टोक्यो में प्राप्त हुई, जब भारत और जापान ने "यूनिकॉर्न" (UNICORN - Unified Complex Radio Antenna) मस्त के संयुक्त विकास हेतु एक क्रियान्वयन समझौता-पत्र (Memorandum of Implementation) पर हस्ताक्षर किए। यह दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों का प्रथम औपचारिक सह-विकास (co-development) है, जिसमें भारत की ओर से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) प्रमुख भूमिका निभा रही है। यह उन्नत संचार प्रणाली नौसैनिक पोतों की स्टील्थ क्षमता को सुदृढ़ करती है तथा "मेक इन इंडिया" पहल के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हुई है। अगस्त 2025 के 15वें शिखर सम्मेलन में दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा सहयोग की इस बढ़ती गति पर संतोष व्यक्त किया।

इसके अतिरिक्त, जापान द्वारा "रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तीन सिद्धांतों" की समीक्षा का भारत ने स्वागत किया है, जिससे भविष्य में रक्षा साझेदारी और अधिक गहन होने की संभावना है। यह दर्शाता है कि रक्षा सहयोग अब केवल प्रतीकात्मक सैन्य अभ्यासों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह ठोस प्रौद्योगिकी सह-विकास की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त कार्यसमूहों का गठन किया गया है, जो उभयनिष्ठ प्रौद्योगिकी क्षेत्रों—जैसे मानवरहित प्रणालियाँ (Unmanned Systems), समुद्री निगरानी उपकरण तथा साइबर सुरक्षा—में सहयोग की संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। यद्यपि भारत-जापान रक्षा व्यापार अभी भी अपेक्षाकृत सीमित है, तथापि नौसैनिक रेडियो एंटीना कार्यक्रम जैसी पहलों से यह स्पष्ट होता है कि दोनों देश अब प्रतीकात्मक सहयोग से आगे बढ़कर ठोस औद्योगिक साझेदारी की दिशा में अग्रसर हैं।

**6. हिंद-प्रशांत रणनीति एवं क्वाड में भूमिका**

भारत और जापान दोनों ही एक "स्वतंत्र, खुले तथा नियम-आधारित हिंद-प्रशांत" (Free and Open Indo-Pacific - FOIP) की परिकल्पना के प्रबल समर्थक रहे हैं। जापान की FOIP रणनीति तथा भारत की "हिंद-प्रशांत महासागर पहल" (Indo-Pacific Oceans Initiative - IPOI) के मध्य गहन तालमेल देखा गया है। भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा नीति, जो पूर्व में "सागर" (SAGAR - Security and Growth for All in the Region, प्रारंभ 2015) के नाम से जानी जाती थी, को मार्च 2025 में मॉरीशस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अद्यतन कर "महासागर" (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions - MAHASAGAR) के रूप में विस्तारित किया गया, जो अब हिंद महासागर क्षेत्र से आगे बढ़कर संपूर्ण ग्लोबल साउथ को समाहित करता है और जापान की रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ अत्यंत सुसंगत है।

क्वाड (Quadrilateral Security Dialogue), जिसमें भारत, जापान, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इस साझेदारी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बहुपक्षीय आयाम है। वर्ष 2017 में इस मंच के पुनरुत्थान के पश्चात्, भारत और जापान दोनों ने क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य तथा आर्थिक प्रभाव के मद्देनज़र समुद्री

सुरक्षा, स्वतंत्र नौवहन तथा नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के संरक्षण हेतु घनिष्ठ सहयोग स्थापित किया है। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों की भूमिका अपरिहार्य है।

प्रधानमंत्री मोदी तथा जापान के प्रधानमंत्री के बीच नियमित द्विपक्षीय भेंट भी होती रही है, जिसका एक उदाहरण 21 सितंबर 2025 को अमेरिका के विलमिंगटन (डेलावेयर) में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन के अवसर पर हुई मुलाक़ात है। इसके अतिरिक्त, 19 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डी.सी. में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान दोनों देशों ने "भारत-जापान विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार आदान-प्रदान वर्ष" (India-Japan Science, Technology and Innovation Exchange Year) की शुरुआत की घोषणा की। यह दर्शाता है कि भारत-जापान साझेदारी अब केवल द्विपक्षीय दायरे तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा वास्तुकला का एक अभिन्न अंग बन चुकी है।

**7. उभरती प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं आर्थिक सुरक्षा सहयोग**

इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में भारत-जापान साझेदारी ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया आयाम ग्रहण किया है। अगस्त 2025 के 15वें शिखर सम्मेलन में दोनों प्रधानमंत्रियों ने "जापान-भारत AI सहयोग पहल" (Japan-India AI Cooperation Initiative) आरंभ की, जिसका उद्देश्य बड़े भाषा मॉडलों (LLMs) सहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग को गहन करना, उद्योग-अकादमिक आदान-प्रदान हेतु मंच स्थापित करना, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन करना, तथा भारत में डेटा केंद्रों (data centers) के विकास एवं संचालन को सुगम बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री इशिबा को भारत द्वारा 19-20 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले "AI इम्पैक्ट समिट" में सम्मिलित होने का निमंत्रण भी दिया। इसके साथ ही "जापान-इंडिया स्टार्टअप सपोर्ट इनिशिएटिव" (JISSI) के माध्यम से दोनों देशों के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य सहयोग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

वैज्ञानिक सहयोग के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 5 जून 2025 को संपन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर 11वीं संयुक्त समिति बैठक में दोनों देशों ने क्वांटम प्रौद्योगिकी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, जैव-प्रौद्योगिकी तथा भू-स्थानिक (geospatial) प्रौद्योगिकियों जैसे नवोदित क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना की। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2025 में वाशिंगटन में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शुरू किए गए "भारत-जापान विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार आदान-प्रदान वर्ष" के अंतर्गत दोनों देशों के शोध संस्थानों के मध्य सहयोग को और सुदृढ़ किया जा रहा है।

आर्थिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में, दोनों देशों ने नवंबर 2024 में उद्घाटन दौर की "भारत-जापान आर्थिक सुरक्षा संवाद" वार्ता के पश्चात्, अगस्त 2025 के शिखर सम्मेलन में औपचारिक "आर्थिक सुरक्षा पहल" की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य अर्धचालकों, गंभीर खनिजों तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। यह पहल "चीन-प्लस-वन" (China+1) रणनीति के अंतर्गत वैश्विक विनिर्माण श्रृंखलाओं में विविधता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दोनों देशों को किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से मुक्त करने में सहायक होगा।

**8. सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं जन-जन संबंध**

भारत-जापान संबंधों की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह केवल सरकारी स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें जन-जन संबंधों तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भी गहराई से समाई हुई हैं। बौद्ध धर्म के माध्यम से स्थापित प्राचीन सांस्कृतिक संबंध आज भी दोनों देशों के बीच सद्भावना का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जापान में भारतीय समुदाय, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जबकि भारत में जापानी निवेश तथा व्यवसायों के विस्तार के साथ-साथ जापानी भाषा तथा संस्कृति के प्रति रुचि भी बढ़ रही है।

शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों, छात्रवृत्तियों तथा विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग समझौतों के माध्यम से दोनों देशों के युवाओं के बीच संपर्क को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें दोनों देशों के नागरिक एक-दूसरे की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत

का अनुभव करने के लिए बड़ी संख्या में यात्रा कर रहे हैं। यह जन-जन संबंध सरकारी स्तर पर होने वाली कूटनीतिक पहलों को दीर्घकालिक स्थायित्व तथा जन-समर्थन प्रदान करते हैं।

**9. चुनौतियाँ एवं भावी दिशा**

भारत-जापान संबंधों की व्यापक प्रगति के बावजूद, इस साझेदारी के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। सर्वप्रथम, द्विपक्षीय व्यापार में असंतुलन एक प्रमुख मुद्दा है, जो स्पष्ट रूप से जापान के पक्ष में झुका हुआ है। भारत के निर्यात की तुलना में आयात कहीं अधिक है, जिसे संतुलित करने के लिए CEPA की समीक्षा तथा भारतीय निर्यात क्षमता को बढ़ाने हेतु ठोस नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है।

द्वितीय, दोनों देशों की रणनीतिक प्राथमिकताओं में कुछ भिन्नताएँ भी देखी जाती हैं। भारत अपनी "रणनीतिक स्वायत्तता" (Strategic Autonomy) की नीति पर दृढ़ रहा है, जिसके कारण वैश्विक मुद्दों, विशेषकर रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों जैसे विषयों पर दोनों देशों के दृष्टिकोण में पूर्ण सामंजस्य नहीं देखा जाता। जापान, जो अमेरिका के साथ घनिष्ठ सुरक्षा गठबंधन में बंधा हुआ है, कई बार पश्चिमी देशों की नीतियों के अधिक निकट खड़ा दिखाई देता है, जबकि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को प्राथमिकता देता है।

तृतीय, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधान, संरक्षणवादी नीतियों का उदय तथा आर्थिक हथियारीकरण (weaponisation of economy) जैसी प्रवृत्तियाँ दोनों देशों के लिए साझा चिंता का विषय हैं, जिनका समाधान संयुक्त प्रयासों के माध्यम से ही संभव है।

इन चुनौतियों के बावजूद, भावी दिशा अत्यंत आशाजनक प्रतीत होती है। दोनों देशों के बीच बढ़ता रणनीतिक विश्वास, प्रौद्योगिकी सहयोग में तीव्र प्रगति, तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा सुरक्षा हितों के मद्देनज़र यह साझेदारी आगामी वर्षों में और अधिक गहन होने की संभावना है। रक्षा सह-विकास परियोजनाओं का विस्तार, अर्धचालक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग, तथा आर्थिक सुरक्षा के लिए संयुक्त रूपरेखा—ये सभी इस बात के संकेत हैं कि भारत-जापान संबंध पारंपरिक कूटनीतिक सीमाओं से आगे बढ़कर एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी का स्वरूप ग्रहण कर चुके हैं।

चतुर्थ, चीन के प्रति दोनों देशों के दृष्टिकोण में भी सूक्ष्म भिन्नताएँ पाई जाती हैं। जहाँ जापान अपनी सुरक्षा नीति में चीन को प्रत्यक्ष चुनौती के रूप में अधिक स्पष्टता से रेखांकित करता है, वहीं भारत सीमा विवाद तथा आर्थिक निर्भरता के बीच संतुलन साधते हुए अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाता है। इसके बावजूद, दोनों देशों के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र तथा नियम-आधारित व्यवस्था की आवश्यकता पर गहन सहमति विद्यमान है, जो क्वाड जैसे मंचों के माध्यम से निरंतर सुदृढ़ हो रही है। भविष्य में दोनों देशों को कुशल मानव संसाधन की आवाजाही, वीज़ा प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा भाषायी बाधाओं को दूर करने जैसे व्यावहारिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग का लाभ आम नागरिकों तथा छोटे एवं मध्यम उद्यमों तक भी प्रभावी रूप से पहुँच सके।

**10. निष्कर्ष**

संक्षेप में कहा जा सकता है कि 2014 के पश्चात् भारत-जापान संबंधों ने गुणात्मक रूप से नई ऊँचाइयाँ प्राप्त की हैं। "विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी" के रूप में इस संबंध का उन्नयन केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं था, अपितु इसने आगामी दशक में रक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में ठोस सहयोग की नींव रखी। वार्षिक शिखर सम्मेलनों की निरंतरता, 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा प्रौद्योगिकी का सह-विकास, तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं आर्थिक सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में गहन सहयोग—ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि भारत-जापान साझेदारी अब एशिया की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियों में से एक बन चुकी है।

आगे की राह में व्यापार असंतुलन तथा रणनीतिक प्राथमिकताओं में भिन्नता जैसी चुनौतियों का समाधान आवश्यक होगा, किंतु दोनों देशों के बीच विद्यमान गहन विश्वास तथा साझा लोकतांत्रिक मूल्य इस बात का आश्वासन देते हैं कि भारत-जापान संबंध आगामी वर्षों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता तथा वैश्विक व्यवस्था के पुनर्गठन में एक निर्णायक भूमिका निभाते रहेंगे। यह साझेदारी न केवल दोनों देशों के राष्ट्रीय

हितों की पूर्ति करती है, बल्कि एक स्वतंत्र, खुले तथा नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है।

## संदर्भ सूची (References)

1. Prime Minister's Office, Government of India — "15th India-Japan Annual Summit Joint Statement: Partnership for Security and Prosperity of our Next Generation," 30 अगस्त 2025।
2. Ministry of Foreign Affairs, Japan — "Japan-India Summit Meeting and Working Dinner," 29 अगस्त 2025।
3. Ministry of External Affairs, Government of India — India-Japan Bilateral Relations Brief, मई 2025।
4. Jain, Purnendu. "Modi–Ishiba Summit Seeks Deeper India–Japan Ties Amid Uncertain Geopolitics." Australian Institute of International Affairs, सितंबर 2025।
5. "India–Japan 2025: A Strategic Summit," Lukmaan IAS Current Affairs, अक्टूबर 2025।
6. IBEF (India Brand Equity Foundation) — "Exploring India Japan Trade and Economic Relations," 2025।
7. भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA), 2011।
8. रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार — भारत-जापान रक्षा सहयोग संबंधी दस्तावेज़।
9. Keerthiraj, and Takashi Sekiyama. 2023. "The Rise of China and Evolving Defense Cooperation between India and Japan." Social Sciences 12(6): 333. https://doi.org/10.3390/socsci12060333
10. Jojin V. John. 2024. "India, Japan and the Indo-Pacific: Evolution, Consolidation and Limitations of the Strategic Partnership." Journal of Asian Security and International Affairs (SAGE). https://doi.org/10.1177/23477970241282067
11. Basrur, Rajesh, and Sumitha Narayanan Kutty. 2022. "Modi's India and Japan: Nested Strategic Partnerships." International Politics 59: 67–89. https://doi.org/10.1057/s41311-021-00288-2
12. Naidu, G. Vijayachandra, and Ishida Yasuyuki. 2019. "India–Japan Defence Ties: Building a Strategic Partnership." Strategic Analysis 43(1): 13–27.
13. Chakraborty, Mohor. 2020. "Navigating the Contours of Maritime Defence Cooperation Between India and Japan: Impulses, Challenges and Opportunities." Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India 16(2): 106-118.
14. "The Changing Dynamics of Japan–India Cooperation: A Case of 'Rule-Based Order' in Indo-Pacific." The Journal of Indian and Asian Studies, World Scientific, 2024।
15. "India's Foreign Policy towards Japan: Special Partnership under Modi." Ritsumeikan Journal of Asia-Pacific Studies, Vol. 38(1)।
16. Khan, Shamshad Ahmed. Changing Dynamics of India Japan Relations: Buddhism to a Special Strategic Partnership. (पुस्तक)
17. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। 2015। India-Japan Vision 2025: Special Strategic and Global Partnership।
18. Ministry of Foreign Affairs, Japan। 2014। Tokyo Declaration for Japan-India Special Strategic and Global Partnership।
19. Institute for National Strategic Studies, National Defense University (USA)। India-Japan Strategic Cooperation and Implications for U.S. Policy, Strategic Perspectives No. 24।
20. "India–Japan Relations," Wikipedia